



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1109]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2009/आषाढ़ 26, 1931

No. 1109]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2009/ASADHA 26, 1931

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

( उच्चतर शिक्षा विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2009

का.आ. 1761(अ).—जबकि, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (दाखिले में आरक्षण), अधिनियम, 2006 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, संचालित अथवा सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण और उससे संबंधित मामलों अथवा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में धारा 3 के तहत व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (क) में यह व्यवस्था की गई है कि धारा 3 के प्रावधान सविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित की गई केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे;

और जबकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला, जिरानिया में स्थापित इस प्रकार की केन्द्रीय शिक्षा संस्था है जो सविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के तहत आती है;

और जबकि, सविधान की छठी अनुसूची के पैरा 12 (कक) के खण्ड (ग) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति संसद के किसी अधिनियम के संबंध में अधिसूचना के द्वारा यह निदेश दे सकते हैं कि यह त्रिपुरा राज्य के किसी स्वायत्त जिले अथवा स्वायत्त क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, अथवा उक्त अधिनियम ऐसे जिले अथवा क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग पर इस प्रकार की अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट अपवादों अथवा संशोधनों की शर्त के अधीन लागू होगा और इस प्रकार का निदेश भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू करने के लिए दिया जा सकता है;

और जबकि, त्रिपुरा विधान सभा ने दिनांक 25 जून, 2008 को अपने सत्र में एक संकल्प स्वीकार किया है जिसमें केन्द्र सरकार से यह देखने के लिए अनुरोध किया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के हितों पर विपरीत प्रभाव न पड़े क्योंकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला सविधान की छठी अनुसूची के तहत त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त परिषद के तहत आने वाले क्षेत्र में आता है;

और जबकि, केन्द्र सरकार को समाज के अनेक वर्गों से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के दाखिलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

और जबकि, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित किये जाने से पहले यह संस्था त्रिपुरा इंजीनियरी कालेज के नाम से जानी जाती थी और इसने त्रिपुरा राज्य द्वारा अपनाई गई आरक्षण नीति के मानकों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 17 प्रतिशत और 31 प्रतिशत के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था कर रखी थी;

और जबकि, परिवर्तन करने के बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिरानिया, अगरतला अखिल भारतीय स्तर पर अपनी 50 प्रतिशत सीटों को भरता है (इन्हें इसके बाद अखिल भारतीय सीट कहा जाता है) तथा शेष सीटों पर त्रिपुरा राज्य के पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है (इन्हें इसके बाद राज्य सीटें कहा जाता है);

इसलिए, अब संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 12 कक के खण्ड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति यह निदेश देती हैं कि केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2007 का 5) के प्रावधान त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद में जिरानिया में स्थित केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं पर लागू होंगे, जो निम्नलिखित संशोधनों के अधीन होंगे, अर्थात्:—

#### संशोधन

1. धारा 3 के अंत में निम्नलिखित परंतुक और व्याख्या को जोड़ा जाएगा:—

“बशर्ते कि त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त परिषद में जिरानिया में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला की कुल राज्य सीटों में से—

(i) 31 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी; और

(ii) 17 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी।

व्याख्या—इस धारा के उद्देश्यार्थ “राज्य सीटों” का अर्थ है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, जिरानिया में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला में अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत दाखिला क्षमता में से पचास प्रतिशत सीटें जो त्रिपुरा राज्य के छात्रों से भरी जाएंगी।

2. धारा 4, खण्ड (क) के अंत में निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए, अर्थात्—

“त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के जिरानिया में स्थित केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों के अतिरिक्त।”

3. धारा 6 में “कैलेण्डर वर्ष, 2007” शब्दों एवं अंकों के स्थान पर “कैलेण्डर वर्ष, 2009” शब्दों एवं अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 1-1/2009-यू.1ए]

सुनिल कुमार, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से  
संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2009

S.O. 1761(E).—Whereas, the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide under section 3 therein for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of citizens, to certain Central Educational Institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas, clause (a) of section 4 of the said Act provides that the provisions of section 3 shall not apply to Central Educational Institutions established in Tribal areas referred to in the Sixth Schedule to the Constitution;

And whereas, the National Institute of Technology, Agartala is a Central Educational Institution established at Jirania which comes in Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Tripura referred to in the Sixth Schedule to the Constitution;

And whereas, clause (c) of paragraph 12AA of the Sixth Schedule to the Constitution provides that the President may, with respect to any Act of Parliament, by notification, direct that it shall not apply to the autonomous district or an autonomous region in the state of Tripura, or shall apply to such district or region or any part thereof, subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification and any such direction may be given so as to have retrospective effect;

And whereas, the Tripura Legislative Assembly in its sitting held on the 25th June, 2008 has adopted a resolution which urges the Central Government to see that the interests of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of citizen are not affected as the National Institute of Technology, Agartala is situated in a place falling in Tripura Tribal Areas Autonomous Council under the Sixth Schedule to the Constitution;

And whereas, the Central Government has received similar requests from various cross sections of the public for the implementation of the said Act for the reservation of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of citizen in admission to the National Institute of Technology, Agartala.

And whereas, prior to its conversion as the National Institute of Technology, the institution was known as the Tripura Engineering College and provided for reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the proportion of seventeen per cent and thirty-one per cent respectively according to the norms of reservation followed by the State of Tripura;

And whereas, on conversion to the National Institute of Technology, at Jirania, Agartala fills fifty per cent of its seats on all India basis (hereinafter referred as All India seats) and the remaining seats from among eligible students from within the State of Tripura (hereinafter referred to as State seats);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of paragraph 12AA of the Sixth Schedule to the Constitution, the President hereby directs that the provisions of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 (5 of 2007) shall apply to Jirania in the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, in respect to Central Educational Institutions situated therein subject to the following modifications, namely :—

#### MODIFICATIONS

1. In Section 3, the following proviso and Explanation shall be inserted at the end, namely :—

“Provided that in the National Institute of Technology, Agartala situated at Jirania in the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, out of total state seats—

- (i) thirty-one per cent seats shall be reserved for the Scheduled Tribes; and
- (ii) seventeen per cent seats shall be reserved for the Scheduled Castes.

**Explanation.**— For the purposes of this clause, the expression “state seats” means fifty per cent of the seats out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty in the National Institute of Technology, Agartala situated at Jirania in the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council which shall be filled from amongst the students within the State of Tripura.”

2. In Section 4, in clause (a), the following words shall be inserted at the end, namely :—

[“other than those Central Educational Institutions situated at Jirania in the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council”].

3. In Section 6, for the words and figures “the calendar year, 2007”, the words and figures “the calendar year, 2009” shall be substituted.

[F. No. 1-1/2009-U. 1A]

SUNIL KUMAR, For and on behalf of the President of India  
Jt. Secy.